



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1469]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2007/अग्रहायण 7, 1929

No. 1469]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2007

(आयकर)

का.आ. 2001(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाला अनुबद्ध प्रोटोकॉल जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 710(अ) दिनांक 18 नवम्बर, 1993 के तहत प्रकाशित किया गया, 3 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी होगा जो उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 8 के अनुसरण में इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद परवर्ती अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि है।

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाले अनुबद्ध प्रोटोकॉल को 1 अप्रैल, 2008 से भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 282/2007/वि.क.प्र./फा.सं. 503/5/2004-वि.क.प्र.]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच 29 अप्रैल, 1992 को भारत में हस्ताक्षरित करार को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच 29 अप्रैल, 1992 को भारत में हस्ताक्षरित करार (आगे ' करार ' के रूप में उल्लिखित किया गया है) को संशोधित करने के लिए प्रोटोकॉल तय करने की इच्छुक भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति हुई है जो करार के अभिन्न अंग होंगे:

अनुच्छेद-1

अनुच्छेद-4 (निवासी) के पैराग्राफ 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

1. इस करार के प्रयोजनार्थ 'संविदाकारी राज्य का निवासी' शब्द का आशय है :
(क) भारत के मामले में : कोई भी व्यक्ति जो भारत के कानूनों के अंतर्गत भारत में अपने मूल निवास, अधिवास, प्रबंधन स्थान अथवा इसी तरह की किसी अन्य कसौटी के कारण कर देने का पात्र हो । तथापि, इस शब्द के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो भारत में स्रोतों से ही आय के संबंध में भारत में कराधान के पात्र हैं ; और

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के मामले में : ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए मौजूद हो, तथा ऐसी कम्पनी जो संयुक्त अरब अमीरात में निगमित हो और जो संयुक्त अरब अमीरात में पूर्णतः प्रबंधित एवं नियंत्रित हो ।

2. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ :

(क) भारत गणराज्य, इसके राजनैतिक उप प्रभाग अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण भारत गणराज्य के निवासी समझे जाएंगे ;

(ख) संयुक्त अरब अमीरात और इसके राजनैतिक उप प्रभागों अथवा स्थानीय सरकारों को संयुक्त अरब अमीरात का निवासी समझा जाएगा;

(ग) संबद्धन के अनुसार सरकारी संस्थाओं को भारत गणराज्य अथवा संयुक्त अरब अमीरात के निवासी के रूप में लिया जाएगा। ऐसी संस्था को सरकारी संस्था समझा जाएगा जिसका सृजन किसी एक संविदाकारी राज्य की सरकार या उसके राजनैतिक उप प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरण/ सरकारों द्वारा किया गया हो, जिसका पूर्ण स्वामित्व तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण/ सरकारों के पास हो जिन्हें इस रूप में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के पारस्परिक करार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(घ) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, आबू धाबी निवेश प्राधिकरण संयुक्त अरब अमीरात के निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पैरा 2 और 3 की संख्या बदलकर क्रमशः 3 और 4 की जाएगी।

अनुच्छेद-2

अनुच्छेद-7 का पैराग्राफ 3 (कारोबार लाभ) के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने के लिए ऐसे खर्च जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं, कटौतियों के रूप में अनुमत होंगे जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, यदि उस राज्य जिसमें स्थायी संस्थापन उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों तथा सीमाओं के अनुसार स्थित हो अथवा अन्यत्र स्थित हो।

अनुच्छेद-3

अनुच्छेद 10 का पैराग्राफ 2 (लाभांश) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

2. तथापि, उस संविदाकारी राज्य में ऐसे लाभांशों पर भी कर लगाया जा सकता है जिसमें लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का लाभग्राही स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित किया गया कर 10% से अधिक नहीं होगा।

अनुच्छेद-4

करार के अनुच्छेद 13 का पैराग्राफ 3 (पूंजीगत अभिलाभ) समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'3. किसी कम्पनी जिसकी सम्पत्ति में किसी संविदाकारी राज्य में स्थित मूलतः प्रचल सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल है, के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

4. कोई कम्पनी जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, में पैराग्राफ 3 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 1, 2, 3, तथा 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगा जिसमें अन्तरणकर्ता एक निवासी है।'

अनुच्छेद-5

अनुच्छेद 24 का पैराग्राफ 1 (सरकार तथा संस्थाओं की आय) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'1. अनुच्छेद 13 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य की सरकार को अन्य संविदाकारी राज्य में ऐसी सरकार द्वारा उस अन्य संविदाकारी राज्य से उद्भूत किसी आय के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी जिसमें पूंजीगत अभिलाभ कर शामिल है।'

अनुच्छेद-6

अनुच्छेद 26 का पैराग्राफ 2 (सम व्यवहार) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'2. किसी संविदाकारी राज्य का कोई ऐसा स्थायी संस्थापन जो कि अन्य संविदाकारी राज्य में एक उद्यम है, पर कराधान उस संविदाकारी राज्य में एक उद्यम जो समान परिस्थितियों तथा समान दशाओं में समान कार्यकलाप करते हैं, पर लगाए गए कराधान की तुलना में उस अन्य संविदाकारी राज्य में उचित रूप से कम नहीं होगा। इस उपबंध को कोई स्थायी संस्थापन जो कि प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे कर की दर से अन्य संविदाकारी राज्य की एक कम्पनी है, के लाभों को प्रभारित करने से किसी संविदाकारी राज्य को निवारक के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी समान कम्पनी के लाभों पर लगाए गए उस कर से अधिक नहीं है और न ही इसे अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के विरोध में माना जाएगा।'

अनुच्छेद-7

करार में 'लाभों के परिसीमन' का एक अनुच्छेद (अनुच्छेद 29) निम्नानुसार शामिल किया जाएगा :

कोई कम्पनी जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, करार के लाभों के लिए पात्र नहीं होगी यदि, इस तरह की किसी कम्पनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अथवा इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इस करार के लाभों का फायदा उठाना था, जो कि अन्यथा उपलब्ध नहीं होंगे। कानूनी कम्पनियों के मामले जिनकी प्रामाणिक कारोबारी गतिविधियां नहीं हैं, वे इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आएंगी।'

अनुच्छेद 29, 30 तथा 31 को क्रमशः अनुच्छेद 30, 31 और 32 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

अनुच्छेद-8

यह करार प्रोटोकॉल का एक अभिन्न अंग होगा। प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त करने के लिए इसके कानून के द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के सम्पन्न होने के बारे में अन्य राज्य को अधिसूचित करेगा। यह प्रोटोकॉल परवर्ती अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा और इसका प्रभाव निम्नवत होगा

(क) संयुक्त अरब अमीरात में :

उस कैलेंडर वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त किया जाता है, के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को अथवा इसके पश्चात प्राप्त आय के संबंध में ;

(ख) भारत में :

उस कैलेंडर वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त किया जाता है, के पश्चात आने वाले 1 अप्रैल को अथवा इसके पश्चात आरंभ होने वाले किसी ' पूर्ववर्ती वर्ष ' में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, जो कि अपनी संबंधित सरकारों की ओर से इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सात के मार्च माह के छब्बीसवें दिन को हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया है, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । तीनों पाठों के अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की ओर से

ह./-

एस. एस. पलानीमाणिकम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (राजस्व)

ह./-

मोहम्मद के. खलफान बिन खिरबाश
वित्त एवं उद्योग राज्य मंत्री

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2007

(INCOME TAX)

S.O. 2001(E).— Whereas the annexed Protocol amending the Agreement between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 710 (E), dated the 18th November, 1993 shall enter into force on the 3rd day of October, 2007, being the date of receipt of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the respective laws for the entry into force of this Protocol, in accordance with Article 8 of the said Protocol.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol annexed hereto amending the Agreement between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1st day of April, 2008.

[Notification No. 282/2007-FTD/F.No. 503/5/2004-FTD]

POONAM DUTT, Jt. Secy.

ANNEXURE

**PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
SIGNED IN INDIA ON 29th APRIL 1992**

The Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab

Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in India on 29th APRIL 1992 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement:

ARTICLE 1

Paragraph 1 of Article 4 (Resident) shall be replaced by the following:

- "1. For the purposes of this Agreement the term "resident of a Contracting State" means:
 - (a) in the case of India: any person who, under the laws of India, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in India in respect only of income from sources in India; and
 - (b) in the case of the United Arab Emirates: an individual who is present in the UAE for a period or periods totaling in the aggregate at least 183 days in the calendar year concerned, and a company which is incorporated in the UAE and which is managed and controlled wholly in UAE.
2. For the purposes of paragraph 1:
 - (a) The Republic of India, its political subdivisions or local authority thereof shall be deemed to be resident of the Republic of India;
 - (b) The United Arab Emirates and its political subdivisions or local governments shall be deemed to be resident of the United Arab Emirates;

- (c) Government institutions shall be deemed, according to affiliation, to be resident of the Republic of India or the United Arab Emirates. Any institution shall be deemed to be a government institution which has been created by the government of one of the Contracting States or of its political subdivisions or local authority / governments, which are wholly owned and controlled directly or indirectly by the government of the Contracting State or political subdivision or local authority / governments which are recognized as such by mutual agreement of the competent authorities of the Contracting States.
- (d) For the purposes of this Article, Abu Dhabi Investment Authority is recognized as a resident of the United Arab Emirates."

Paragraphs 2 and 3 shall be renumbered as 3 and 4 respectively.

ARTICLE 2

Paragraph 3 of Article 7 (Business profits) shall be replaced by the following.

"3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State."

ARTICLE 3

Paragraph 2 of Article 10 (Dividends) shall be replaced by the following:

"2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10%."

ARTICLE 4

Paragraph 3 of Article 13 (Capital Gains) of the Agreement shall be replaced by the following:

"3. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

4. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 3 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1,2,3 and 4 above shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident."

ARTICLE 5

Paragraph 1 of Article 24 (Income of Government and Institutions) shall be replaced by the following:

"1. Notwithstanding the provisions of Article 13, the Government of one Contracting State shall be exempt from tax, including capital gains tax, in the other Contracting State in respect of any income derived by such Government from that other Contracting State."

ARTICLE 6

Paragraph 2 of Article 26 (Nondiscrimination) shall be replaced by the following:

"2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that

other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7."

ARTICLE 7

An Article on 'Limitation of Benefits' (Article 29) shall be included in the Agreement, as under:

"An entity which is a resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of this Agreement if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such entity was to obtain the benefits of this Agreement that would not be otherwise available. The cases of legal entities not having bonafide business activities shall be covered by this Article."

Articles 29, 30 and 31 shall be renumbered as Articles 30, 31 and 32 respectively.

ARTICLE 8

This Protocol shall form an integral part of the Agreement. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the proceedings required by its law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:-

(a) in the United Arab Emirates :

in respect of income derived on or after the 1st January next following the calendar year in which the Protocol enters into force ;

(b) in India :

in respect of income arising in any "previous year" beginning on or after 1st April next following the calendar year in which the Protocol enters into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this twenty sixth day of March 2007 in English, Arabic and Hindi languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of
the Republic of India

Sd./-

S. S. Palanimanickam
Minister of State for Finance (Revenue)

For the Government of the
United Arab Emirates

Sd./-

Mohammed K. Khalfan Bin Khirbash
Minister of State for Finance and Industry